उत्तराखंड की खनन नीति का डंका, दूसरे राज्य भी अपनाने को मजबूर

खनन व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीक का मॉडल बना मिसाल

किच्छा। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में ऐसी नीतिगत पहल की है, जिसने देश के दूसरे राज्यों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के इस्तेमाल, राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन पर शिकंजा कसने की दिशा में उठाए गए कदम अब दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की खनन नीति से प्रभावित होकर अन्य राज्य भी इसकी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें अपने यहां लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में जम्मू कश्मीर के बाद अब छत्तीसगढ़ की खनन टीम यहां अध्ययन के लिए आई हुई हैद्य उत्तराखंड की खनन नीति में पारदर्शिता, तकनीक निगरानी का सबसे मजबूत हथियार बना है।

उत्तराखंड में खनन गतिविधियों को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर खनन निदेशक राजपाल लेघा ने ऑनलाइन प्रक्रियाओं, ई-नीलामी और तकनीकी निगरानी को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य खनन पट्टों की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने के साथ ही सरकारी राजस्व को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना



है। तकनीक आधारित निगरानी से खनन क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता भी बढ़ी है। उत्तराखंड में खनन तो हो रहा था परंतु राजस्व नहीं बढ़ पा रहा थाद्य और खनन निदेशक राजपाल लेघा ने इसको एक चुनौती के रूप में लेकर उत्तराखंड की खनन नीति से राजस्व बढ़ाने के साथ अवैध खनन पर भी शिकंजा कसा है।

खनन नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सरकारी राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को नियंत्रित और नियमबद्ध करना भी है। उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है, ताकि नीति का लाभ वास्तविक रूप से दिखाई दे।उत्तराखंड के खनन मॉडल से दूसरे राज्यों को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है।

पर्वतीय और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण उत्तराखंड में खनन का प्रबंधन आसान नहीं है। ऐसे में यहां तैयार की जा रही व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खनन नीति में पारदर्शिता, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और सख्त निगरानी को एक साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो खनन क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सकता है। जिसमें काफी हद तक उत्तराखंड खनन विभाग ने सफलता हासिल की हैद्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खनन नीति में पारदर्शिता पर विशेष जोर देते रहे हैं और इसको अमली जामा पहनाया है उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा ने अपनी कुशल कार्य प्रणाली से।

उत्तराखंड की खनन नीति को मिल रही यह स्वीकार्यता राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब जरूरत इस बात की है कि नीति को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उसका जमीनी क्रियान्वयन और मजबूत किया जाए। यदि सरकार अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने, पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने और राजस्व व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने में सफल होती है, तो उत्तराखंड देश के सामने एक आदर्श और अनुकरणीय खनन मॉडल पेश कर सकता है। जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खनन निदेशक राजपाल लेघा लगातार प्रयास कर रहे हैं